

मैसर्स दामोदर घाटी निगम

बनाम

बिहार राज्य

(बी. पी. सिन्हा, सी. जे., एस. जे. इमाम. ए. के. सरकार, . सुब्बा राव और जे. सी. शाह, जे. जे.)

बिक्री कर-देयता-ठेकेदार को उपकरण और मशीनरी की आपूर्ति के लिए समझौता-यदि कोई बिक्री या किराया-परीक्षण-बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947 (1947 का 19)। 2 (छ), 13 (5), 25।

अपीलार्थी निगम का निर्धारण बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 13 (5) के तहत मशीनरी और उपकरणों की कीमत पर बिक्री कर के रूप में किया गया था, जो लगभग रु। 42,63,305, एक समझौते के आधार पर दो ठेकेदार फर्मों को आपूर्ति की गई जो उन्होंने एक बांध के निर्माण के लिए उनके साथ किया था। समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि आपूर्ति की गई मशीनरी और उपकरणों की कीमत का भुगतान ठेकेदारों द्वारा किया जाना था और जब तक ऐसा नहीं किया जाता, तब तक वे निगम की संपत्ति बने रहेंगे। यह भी सहमति हुई कि निगम काम पूरा होने के बाद उनके अवशिष्ट मूल्य पर उन्हें अपने हाथ में ले लेगा, जिसकी गणना समझौते में निर्धारित तरीके से की जाएगी, बशर्ते कि संचालन की अवधि के दौरान उनकी उचित देखभाल की गई हो; और यदि ठेकेदारों ने पहले ऐसा चुना हो, अगर उन्हें अधिशेष घोषित किया गया हो और सलाहकार अभियंता द्वारा प्रमाणित किया गया हो। मूल्य का भुगतान 18 समान किशतों में किया जाना था, जिनमें से दो-तिहाई किसी भी मामले में प्राप्त किया जा सकता था, और उसके बाद निगम को अवशिष्ट मूल्य पर पहुंचने के लिए मूल्यहास के मूल्यांकन के बाद उन्हें लेने

की तारीख या तिथियों पर विचार करना था। यदि उपकरणों का अवशिष्ट जीवन पक्षों द्वारा निर्धारित मानक जीवन के एक तिहाई से कम हो जाता है तो निगम इसे संभालने के लिए बाध्य नहीं था।

ठेकेदारों को अपनी लागत पर उन्हें आपूर्ति किए गए स्पेयर पार्ट्स के स्टॉक को फिर से भरना था। अपीलार्थी का मामला यह था कि समझौते द्वारा दर्शाया गया लेन-देन अधिनियम के अर्थ के भीतर बिक्री नहीं था। बिक्री कर अधिकारियों ने इसके खिलाफ निर्णय दिया और एकमात्र सवाल जिसे अंततः राजस्व बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत उच्च न्यायालय को भेजा गया था, वह यह था कि क्या उपकरण और मशीनरी में संपत्ति ठेकेदारों को दी गई थी और लेनदेन बिक्री के बराबर था। उच्च न्यायालय ने सकारात्मक रूप में प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि लेन-देन अधिनियम की धारा 2 (छ) के अर्थ के भीतर एक बिक्री थी। उच्च न्यायालय ने आवश्यक प्रमाण पत्र को अस्वीकार कर दिया, अपीलार्थी ने इस अदालत द्वारा दी गई विशेष अनुमति द्वारा अपील की।

अभिनिर्धारित किया कि अपील उच्च न्यायालय में बहस किए गए प्रश्न तक ही सीमित होनी चाहिए। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि, एक कर कानून के तहत अपनी सलाहकार क्षमता में काम करते हुए, उच्च न्यायालय उसे संदर्भित प्रश्न या उसके द्वारा बुलाए गए संदर्भ से आगे नहीं जा सकता है। यह अपील विशेष अनुमति द्वारा की गई थी जिससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता था और विवाद का दायरा उच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी रूप से उठाए जाने से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष समझौता केवल किराए पर लेने या स्थगित भुगतान पर खरीद का अनुबंध है, दो गुना परीक्षण यह है कि (1) क्या अवक्रेता माल खरीदने के लिए बाध्य है और (2) क्या उसे अनुबंध के निर्वाह के दौरान

किसी भी समय माल वापस करने का अधिकार है। प्रत्येक मामले में जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए वह समझौते का सार है न कि इसकी श्रेणी का वर्णन करने वाले शब्द। हेल्बी बनाम मैथ्यूज और अन्य, (1895) ए. सी. 471, संदर्भित। इस प्रकार, इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि पक्षों के बीच समझौते की शर्तों पर तत्काल मामले में लेनदेन स्पष्ट रूप से पुनर्खरीद के विकल्प के साथ आस्थगित भुगतान पर एक बिक्री थी, न कि केवल काम पर रखने का अनुबंध।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार : 1959 की सिविल अपील सं. 285

पटना उच्च न्यायालय के 13 जुलाई, 1956 के निर्णय और डिक्री की विशेष अनुमति द्वारा अपील जो कि 1954 के एम. जे. सी. सं. 404 में पारित की गई।

अपीलार्थियों की ओर से भारत के महान्यायवादी एम. सी. सीतलवाड़ और एस. पी. वर्मा।

प्रतिवादी के लिए ए. वी. वी. विश्वनाथ शास्त्री, बुरेश अग्रवाल और डी. पी. सिंह।

1960, 21 नवंबर।

न्यायालय का निर्णय सिन्हा, सी. जे. द्वारा दिया गया।

यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 25 (1) के तहत एक संदर्भ का निपटारा करते हुए पटना उच्च न्यायालय के 13 जुलाई, 1956 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसे इसके बाद राजस्व बोर्ड, बिहार द्वारा बनाए गए अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

इस मामले के तथ्य कभी भी विवाद में नहीं रहे हैं और जल्द ही निम्नलिखित रूप में बताए जा सकते हैं। अपीलार्थी दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 का XIV) के तहत निगमित एक निगम है और इसके बाद इसे निगम के रूप में संदर्भित किया जाएगा। यह एक बहुउद्देशीय निगम है, जिसका एक उद्देश्य बाढ़ को नियंत्रित करने और

संग्रहीत पानी का उपयोग बिजली उत्पादन के उद्देश्यों के लिए बिहार और बंगाल में कई बांधों का निर्माण करना है। इनमें से एक बांध बिहार के हजारीबाग जिले में स्थित कोनार बांध है। उपरोक्त बांध के निर्माण के लिए निगम ने मेसर्स हिंद कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग कंपनी के साथ एक समझौता किया। लिमिटेड ने 24 मई, 1950 को उन्हें उपरोक्त उद्देश्य के लिए ठेकेदार नियुक्त किया। इसके बाद उन्हें ठेकेदारों के रूप में संदर्भित किया जाएगा। बांध के डिजाइन में बदलाव के परिणामस्वरूप, एक पूरक समझौता करना आवश्यक हो गया और 10 मार्च, 1951 को मूल समझौते के भाग II के खंड 8 में संशोधन किया गया और एक नए खंड 8 को प्रतिस्थापित किया गया। समझौते के नए खंड 8 के तहत, जैसा कि संशोधित किया गया है, निगम ठेकेदारों को ऐसे उपकरण उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ जो उपरोक्त निर्माण के लिए आवश्यक और उपयुक्त थे। ठेकेदारों से निगम द्वारा इस प्रकार उपलब्ध कराए गए उपकरण और मशीनरी के लिए भुगतान की गई वास्तविक कीमत ली जाती है, जिसमें माल ढुलाई और सीमा शुल्क, यदि कोई हो, के साथ-साथ परिवहन की लागत भी शामिल है, लेकिन बिक्री कर को छोड़कर। निगम द्वारा ठेकेदारों को इस प्रकार आपूर्ति किए गए उपकरणों को दो समूहों, समूह ए और समूह बी में वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि अनुसूची संख्या 2 में विस्तृत है। समूह ए में मशीनरी को ठेकेदारों से निगम द्वारा उनके "अवशिष्ट मूल्य" पर काम पूरा करने के बाद लिया जाना था, जिसकी गणना समझौते में निर्धारित तरीके से की जानी थी। समूह बी में मशीनरी को ठेकेदारों द्वारा इसकी पूरी कीमत का भुगतान करने के बाद उनकी संपत्ति बनना था। समूह बी में मशीनरी के बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समूह के बारे में कोई विवाद नहीं है, ठेकेदारों ने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि समूह बी मशीनरी उन्हें बेच दी गई थी। दोनों पक्षों के बीच अब जो विवाद बना हुआ है, वह समूह ए के तंत्र से संबंधित है

12 अगस्त, 1952 को हजारीबाग के बिक्री कर अधीक्षक ने अप्रैल, 1950 से मार्च, 1952 की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 13 (5) के तहत निगम का आकलन किया। कर मांग का विवरण निर्धारित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि राशि विवाद में नहीं है। नीचे दिए गए अधिकारियों और इस न्यायालय में जो तर्क दिया गया था, वह यह था कि विचाराधीन लेन-देन अधिनियम के अर्थ के भीतर "बिक्री" के बराबर नहीं था। अधीक्षक ने निगम की ओर से उठाए गए इस तर्क को खारिज कर दिया कि वह मशीनरी उप के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठेकेदारों से संपर्क किया। निगम ने मूल्यांकन के उक्त आदेश के खिलाफ बिक्री कर उपायुक्त के पास अपील की। 5 मई, 1953 के अपने आदेश द्वारा, उपायुक्त ने अधिनियम के तहत अपने दायित्व के बारे में अपीलार्थी के तर्क को खारिज कर दिया, लेकिन मूल्यांकन में कुछ संशोधन किए, जो हमारे सामने विवादग्रस्त बिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। अधिनियम के आधार पर निगम की दलीलों को दरकिनार करते हुए उपायुक्त ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त समझौते के समूह में उपकरणों की आपूर्ति बिक्री के बराबर है और यह किराया नहीं है; समझौते में निर्धारित शर्तों पर उपकरणों के "अधिग्रहण" के लिए समझौते में शर्त इसके सार में थी। अधिनियम के अर्थ के भीतर "विक्रेता"। निगम ने राजस्व बोर्ड, बिहार को अधिनियम की धारा 24 के तहत अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। राजस्व बोर्ड ने 1 अक्टूबर, 1953 के अपने प्रस्ताव द्वारा संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया और नीचे दिए गए अधिकारियों के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद निगम ने राजस्व बोर्ड को एक आवेदन दिया। अधिनियम की धारा 25 पटना में उच्च न्यायालय को निम्नलिखित प्रश्नों को संदर्भित करने के लिए, अर्थात् (क) अधिनियम की धारा 13 (5) के तहत मूल्यांकन बनाए रखने योग्य है या नहीं, (ख) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि

अनुसूची क में शामिल माल में संपत्ति ठेकेदारों को दी गई थी और लेनदेन बिक्री के बराबर था, और (ग) क्या समझौते की शर्तें ठेकेदारों के साथ बिक्री लेनदेन के बराबर हैं और निगम द्वारा अधिग्रहण पुनः खरीद के बराबर है। यह आवेदन 22 दिसंबर, 1953 को किया गया था, लेकिन जब 20 मई, 1954 को राजस्व बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में संदर्भ देने का आवेदन आया और पक्षों की सुनवाई के बाद निगम के वकील ने प्रस्तावित संदर्भ से प्रश्न (ए) और (सी) वापस लेने के लिए बोर्ड से अनुमति मांगी और बोर्ड ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"विद्वान अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ता से संदर्भ से प्रश्न (ए) और (सी) छोड़ने के लिए अनुमति मांगी जाती है। छुट्टी दी जाती है। केवल प्रश्न (ख) उच्च न्यायालय को संदर्भित करने के लिए बचा है। "इस प्रकार केवल ऊपर दिए गए प्रश्न (ख) को अपने निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया था। पक्षकारों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, रामास्वामी, सी. जे. और राज किशोर प्रसाद, जे. ने संदर्भ को सुना और 13 जुलाई, 1956 के अपने निर्णय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संदर्भ का उत्तर सकारात्मक में दिया जाना चाहिए, अर्थात्, विचाराधीन लेन-देन अधिनियम की धारा 2 (जी) के अर्थ के भीतर एक बिक्री के बराबर है।"

इसके बाद निगम ने संविधान के अनुच्छेद 132 (1) के तहत एक आवेदन किया और प्रार्थना की कि उच्च न्यायालय "भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दे और आवश्यक प्रमाण पत्र प्रदान करे कि यह मामला अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए एक उपयुक्त मामला है।" उपरोक्त संदर्भ पर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए हमले के आधार को उठाने के अलावा, निगम ने आवेदन की

सुनवाई के समय अन्य प्रश्न उठाए हैं जो उच्च न्यायालय के 31 जनवरी, 1957 के निर्णय और आदेश के निम्नलिखित उद्धरण से दिखाई देते हैं।

"याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह स्वीकार किया कि मामला संविधान के अनुच्छेद 133 (1) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। लेकिन तर्क यह है कि संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत अनुमति दी जा सकती है क्योंकि इस मामले में शामिल संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून का एक बड़ा सवाल है। हम इस तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं। हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि इस मामले में शामिल संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल है। इस मुद्दे पर सवाल विशुद्ध रूप से बिहार बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (जी) के निर्माण का मामला था और उस सवाल का फैसला इस अदालत ने बिहार राज्य के पक्ष में और याचिकाकर्ता के खिलाफ किया था। याचिकाकर्ता की ओर से अब यह तर्क दिया जाता है कि बिहार बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (जी) के प्रावधान संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भ में ऐसे किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया गया था या निर्णय नहीं लिया गया था। इसलिए हम यह नहीं मानते कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 132 (1) की आवश्यकताओं को पूरा करता है और याचिकाकर्ता इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए प्रमाण पत्र देने का हकदार नहीं है।"

तदनुसार आवेदन खारिज कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहने के बाद निगम ने इस न्यायालय का रुख किया

और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त की।
31 मार्च, 1958 को अनुमति दी गई थी।

हालांकि अधिनियम की धारा 25 के तहत उच्च न्यायालय के निर्णय का दायरा सीमित है, निगम ने विवाद के कुछ अतिरिक्त बिंदु उठाए हैं, जो उच्च न्यायालय के निर्णय का हिस्सा नहीं थे। इस प्रश्न के अलावा कि क्या विचाराधीन लेन-देन अधिनियम के अर्थ के भीतर एक बिक्री के बराबर है, अपीलार्थी की ओर से मामले का बयान हमले के निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों को उठाता है, अर्थात्, (1) कि निगम अधिनियम के अर्थ के भीतर एक विक्रेता नहीं है, (2) कि अधिनियम की धारा 2 (छ) का परंतुक बिहार विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और (3) कि यह अधिनियम स्वयं बिहार विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह विधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 की अनुसूची 7 की सूची 2 में प्रविष्टि 48 के दायरे से बाहर है। इसलिए, प्रत्यर्थी की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि इस न्यायालय में निगम के लिए हमले के अतिरिक्त आधार खुले नहीं थे। इसलिए, पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या ऊपर दिए गए हमले के अतिरिक्त आधार निगम के लिए खुले हैं। हमारी राय में, वे अतिरिक्त आधार खुले नहीं हैं। उन्हें कार्यवाही के किसी भी चरण में नीचे के अधिकारियों या उच्च न्यायालय में कभी नहीं उठाया गया था। यह न्यायालय अधिनियम की धारा 25 के तहत उच्च न्यायालय के फैसले पर अपील कर रहा है। उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष पर पहुँचने में केवल एक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा था। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कर कानून के तहत अपनी सलाहकार क्षमता में कार्य करने वाला उच्च न्यायालय उसे संदर्भित प्रश्नों से परे या उसके द्वारा बुलाए गए संदर्भ पर नहीं जा सकता है। इस न्यायालय में अपील का दायरा, विशेष अनुमति द्वारा भी, उस विवाद के दायरे से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी रूप से उठाया जा सकता था। यह स्पष्ट है कि उच्च

न्यायालय राजस्व बोर्ड द्वारा दिए गए संदर्भ के परिणामस्वरूप वास्तव में उसके समक्ष प्रश्न के अलावा किसी अन्य मामले पर अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकता था। इसलिए, प्रारंभिक आपत्ति की अनुमति दी जानी चाहिए और अपील इस सवाल तक सीमित होनी चाहिए कि क्या इस मामले में विचाराधीन लेनदेन अधिनियम के अर्थ के भीतर बिक्री के बराबर है।

यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच इस विवाद को अनुबंध की शर्तों के संदर्भ में ही हल करना होगा। यथा संशोधित समझौते का खंड 8 एक बहुत ही जटिल है जो वर्तमान में निम्नलिखित उद्धरणों से दिखाई देगा, जो उस खंड के प्रासंगिक भाग हैं: -

"निगम ठेकेदार के उपयोग के लिए अपने ऐसे उपकरण किराए पर ले सकता है या उपलब्ध करा सकता है जो निर्माण के लिए उपयुक्त हों। इस प्रकार उपलब्ध कराए गए उपकरणों के लिए निगम द्वारा भुगतान की गई वास्तविक कीमतें, जिसमें माल ढुलाई, बीमा और सीमा शुल्क, यदि कोई हो, और साइट पर इसके परिवहन की लागत शामिल है, लेकिन बिक्री कर जैसे स्थानीय, नगरपालिका, राज्य या केंद्रीय कर को छोड़कर, ठेकेदार से लिया जाएगा और उपकरण निगम की संपत्ति बने रहेंगे जब तक कि ठेकेदार से उनकी पूरी कीमतें प्राप्त नहीं हो जाती हैं। ठेकेदार के उपयोग के लिए उधार दिए गए उपकरण, यदि कोई हों, तो उनसे पारस्परिक रूप से सहमत होने के लिए किराए पर लेने की शर्तों पर शुल्क लिया जाएगा; ऐसी शर्तों में पूंजीगत लागत पर ब्याज और उपकरण का मूल्यहास शामिल होगा।

निगम ठेकेदार को नीचे अनुसूची संख्या 2, समूह ए और समूह बी में उल्लिखित मशीनरी की आपूर्ति करेगा।

इसके बाद समूह ए में ऐसी मशीनरी की संख्या और उसकी अनुमानित लागत के साथ मशीनरी की कई वस्तुओं का विवरण क्रमबद्ध किया गया है। इस समूह ए में, चौदह वस्तुएँ हैं जिनमें से केवल पहले का उल्लेख करना आवश्यक है, अर्थात्, सहायक उपकरण के साथ चार उत्खनन यंत्र जिनका मूल्य लगभग रु। 12,46,390; और नहीं। 14, एक अन्य मॉडल के दो उत्खनन, जिनकी लागत लगभग रु। 3,35,000। समूह ए में मशीनरी की कुल अनुमानित लागत रु। 42,63,305। फिर समूह बी में मशीनरी के विवरण का पालन करें, जिसकी अनुमानित लागत रु। 21,84,148। फिर समूह ए में शामिल उपकरणों के संबंध में कुछ शर्तों का पालन करें, इन शर्तों में: -

"निगम ठेकेदार मद 1 और 14 से कार्य के पूरा होने पर कार्य किए गए घंटों की वास्तविक संख्या के आधार पर गणना किए गए अवशिष्ट मूल्य पर पदभार ग्रहण करेगा। यह मानते हुए कि कुल जीवन 30,000 घंटे है और यह मानते हुए कि इसके संचालन की अवधि के दौरान मशीनरी की उचित देखभाल की जाएगी। इस समूह की शेष वस्तुओं को निगम द्वारा उनके अवशिष्ट मूल्य पर काम किए गए घंटों की वास्तविक संख्या और ऐसी मशीनरी के मानक जीवन को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा, जिसके लिए यू. एस. औद्योगिक राजस्व ब्यूरो द्वारा अंतिम बार जारी की गई अनुसूची एफ, आयकर उद्देश्य के लिए स्वीकार्य संभावित उपयोगी जीवन और मूल्यहास दरों पर (17 मार्च, 1949 के इंजीनियरिंग समाचार रिकॉर्ड के अनुसार) एक आधार के रूप में काम करेगी, बशर्ते कि अपने संचालन की अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा मशीनरी की उचित देखभाल की जाएगी। बशर्ते कि मशीनरी के ऐसे अवशिष्ट मूल्य का आकलन निगम और ठेकेदार के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और दोनों पक्षों के बीच

मतभेद की स्थिति में मामले का निपटारा किसी तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जाएगा, जिस पर निगम और ठेकेदार दोनों सहमत होंगे।

इस समूह में शामिल वस्तुओं को या तो काम पूरा होने पर या यदि ठेकेदार चाहे तो पहले की तारीख में निगम द्वारा ठेकेदार से ले लिया जाएगा, बशर्ते कि बाद के मामले में उपकरण निगम द्वारा केवल तभी लिए जाएंगे जब उन्हें कोनार में अधिशेष घोषित किया जाएगा और ऐसी घोषणा निगम द्वारा प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर सलाहकार अभियंता द्वारा विधिवत प्रमाणित की जाएगी।

31 दिसंबर, 1950 को या उससे पहले ठेकेदार को दी गई मशीनरी के संबंध में, उनकी लागत ठेकेदार से जनवरी, 1951 से शुरू होने वाली अठारह समान किशतों में वसूल की जाएगी और इस समूह की मशीनरी में शामिल शेष वस्तुओं के संबंध में, उनकी लागत ठेकेदार से जुलाई, 1951 से शुरू होने वाली अठारह समान किशतों में वसूल की जाएगी, बशर्ते कि इन शेष वस्तुओं को अंतिम निर्दिष्ट तिथि से पहले ठेकेदार को सौंप दिया गया हो। प्रदान किया गया

(क) कि इन उपकरणों की कुल वास्तविक कीमत जो अस्थायी रूप से रु। 42,63,305 उपरोक्त खंड 1 के पहले पैरा के अनुसार ठेकेदार से प्रभार्य होगा।

(b) कि कुल लागत के लगभग दो तिहाई या रु। इन उपकरणों के कारण ठेकेदार से लगभग अट्ठाईस लाख तैंतीस हजार रुपये की वसूली की गई है, निगम उस तारीख या तारीख पर विचार करेगा जब वह ठेकेदार द्वारा अभी भी उपयोग किए जा रहे उपकरणों को अपने नियंत्रण में ले सकता है, यह आकलन करेगा कि वे पहले से ही किस हद तक मूल्यह्रास हो चुके हैं और इस तरह उनके अवशिष्ट मूल्य पर पहुंच सकते हैं; और

(ग) कि इन उपकरणों के कारण ठेकेदार द्वारा या उसे देय राशि की वसूली या वापसी का निर्णय केवल तभी किया जाएगा जब निगम पूरी तरह से संतुष्ट हो कि निगम को सौंपने के समय उनका अवशिष्ट जीवन किसी भी परिस्थिति में उनके संबंधित मानक जीवन के एक तिहाई से कम नहीं होगा जैसा कि निगम और ठेकेदार द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।

फिर समूह 'बी' के संबंध में नियमों और शर्तों का पालन करें जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। इसके बाद, निम्नलिखित शर्तें दिखाई देती हैं:-"निगम द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध कराए गए उपकरणों के संबंध में, चाहे वे समूह ए या बी में हों।

निम्नलिखित शर्तें सभी उपकरणों पर लागू होंगी, अर्थात्, उपरोक्त समूह ए और बी में शामिल और अन्य, यदि कोई हों;

(क) ठेकेदार उपकरणों की प्रत्येक वस्तु के संबंध में अलग-अलग उचित मशीन कार्ड बनाए रखेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा कि मशीन ने तारीखों और अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ मिलकर काम करने के वास्तविक घंटों की संख्या कितनी है।

(ख) ठेकेदार ऐसे सभी उपकरणों को अच्छी स्थिति में बनाए रखेगा और निगम के मुख्य अभियंता द्वारा आवश्यक सभी संयंत्रों और मशीनरी को नियमित रूप से और कुशलता से सेवा देगा, जिसे व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से ऐसे सभी संयंत्रों और उपकरणों और उनके संबंध में बनाए गए मशीन कार्ड का पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(ग) निगम द्वारा ऋण या किराए पर उपलब्ध कराई गई किसी भी वस्तु को किसी भी परिस्थिति में कार्य स्थल से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि निगम द्वारा ठेकेदार से उसकी पूरी लागत वसूल नहीं की जाती है और उसके बाद केवल तभी जब

सलाहकार अभियंता की राय में ऐसी वस्तु या वस्तुओं को हटाने से काम के संतोषजनक अभियोजन में बाधा आने की संभावना नहीं है।

इसी तरह ठेकेदार से संबंधित उपकरण या सामग्री की कोई भी वस्तु, लेकिन जिसकी लागत के लिए निगम द्वारा धन आगे बढ़ाया गया है, किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में कार्य स्थल से तब तक नहीं हटाई जाएगी जब तक कि निगम द्वारा ठेकेदार से इस तरह की अग्रिम राशि की राशि बरामद नहीं हो जाती है और उसके बाद यदि सलाहकार अभियंता की राय में ऐसी वस्तु या वस्तुओं को हटाने से काम के संतोषजनक अभियोजन में बाधा आने की संभावना नहीं है।

निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पुर्जों को ठेकेदार को कार्यकारी अभियंता, कोनार द्वारा जब भी ठेकेदार द्वारा आवश्यक होगा, एक प्रमाण पत्र के साथ जारी किया जाएगा कि उसे पहले जारी किए गए पुर्जों का वास्तव में उन मशीनों पर उपयोग किया गया है जिनके लिए वे अभिप्रेत थे।

(घ) जब भी इस प्रावधान के अनुसार ठेकेदार को पुर्जे जारी किए जाते हैं, तो माल दुलाई, बीमा और सीमा शुल्क सहित उनकी वास्तविक कीमतें, लेकिन भंडारण और हैंडलिंग शुल्क को छोड़कर, उसके खिलाफ डेबिट की जाएंगी और उसके अगले पखवाड़े के बिल से वसूल की जाएंगी।

(च) ठेकेदार को अग्रिम रूप से अतिरिक्त पुर्जों की खरीद की योजना बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए, निगम उसे उन सभी पुर्जों की पूरी सूची प्रदान करेगा जिन्हें उसने ठेकेदार को आपूर्ति करने के लिए उपकरण के लिए खरीदा या आदेश दिया है।

ऊपर उद्धृत भागों में विचाराधीन लेन-देन के संबंध में प्रासंगिक नियम और शर्तें हैं, जहां तक इस मामले के उद्देश्य के लिए उन्हें जानना आवश्यक है। यह ध्यान दिया जाएगा

कि निगम ने ठेकेदारों को समूह ए में विस्तृत विभिन्न प्रकार की मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराए हैं, जिनका अनुमानित मूल्य रु। 42,63,000 विषम, जिसके लिए निगम द्वारा माल ढुलाई, बीमा, सीमा शुल्क आदि सहित भुगतान की गई कीमत उनसे ली जानी है। लेकिन ठेकेदारों को इस तरह से उपलब्ध कराई गई मशीनरी और उपकरण तब तक निगम की संपत्ति बने रहेंगे जब तक कि ठेकेदारों से उनकी पूरी कीमत नहीं मिल जाती। यह भी उल्लेखनीय है कि समझौता समझौते के उपरोक्त भाग और ठेकेदारों को दिए गए उपकरणों के बीच अंतर करता है, जिसके संबंध में ठेकेदारों से पूंजी लागत पर ब्याज और उपकरणों के मूल्यहास सहित काम पर रखने के संदर्भ में शुल्क लिया जाना था। इस प्रकार स्पष्ट रूप से पक्षों के बीच समझौते में उनके बीच दो प्रकार के लेन-देन पर विचार किया गया, अर्थात् (1) निगम द्वारा ठेकेदारों को मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति और (2) निगम द्वारा ठेकेदारों को आपूर्ति की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों के संबंध में उनके बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर अन्य उपकरणों को किराए पर लेने पर ऋण। एक और शर्त है कि निगम ठेकेदारों की वस्तुओं 1 और 14, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित, और समूह ए में अन्य वस्तुओं को उनके "अवशिष्ट मूल्य" पर लेगा, जिसकी गणना मशीनरी और उपकरणों के विवरण के बाद पैराग्राफ में बताए गए आधार पर की जाएगी। लेकिन एक शर्त जोड़ी गई है कि "अधिग्रहण" इस शर्त पर निर्भर करता है कि इसके संचालन की अवधि के दौरान मशीनरी की ठीक से देखभाल की जाएगी। निगम द्वारा अधिग्रहण के लिए एक अतिरिक्त शर्त है, अर्थात्, जिस कार्य के लिए वे अभिप्रेत थे, वह ठेकेदारों की पसंद पर पूरा किया गया था, या पहले, बशर्ते कि उन्हें कोनार बांध के निर्माण के उद्देश्यों के लिए अधिशेष घोषित किया गया हो और इसलिए सलाहकार अभियंता द्वारा प्रमाणित किया गया हो। इसलिए, समूह बी की तरह मशीनरी और उपकरणों को लेना बिना शर्त समझौता नहीं है। 42,63,305 ठेकेदारों द्वारा 18 समान किशतों में देय है। इस प्रकार ठेकेदारों से वसूल

की जाने वाली कुल लागत में से दो-तिहाई, अर्थात् रु। 28,42,000 लगभग, किसी भी मामले में महसूस किया जाना चाहिए। निगम द्वारा उपकरणों की आपूर्ति के कारण ठेकेदारों से उपरोक्त दो-तिहाई राशि प्राप्त होने के बाद, निगम को इस बात का आकलन करने के बाद उपकरण के "अधिग्रहण" की तारीख या तिथियों पर विचार करना पड़ा कि परियोजना पर काम करने के परिणामस्वरूप इसका मूल्य किस हद तक कम हुआ है ताकि इसके "अवशिष्ट मूल्य" पर पहुंचा जा सके। मूल्य के एक तिहाई या ऐसी अन्य राशि की वापसी जो "अवशिष्ट मूल्य" के रूप में निर्धारित की जा सकती है, इस शर्त पर निर्भर करेगी कि निगम पूरी तरह से संतुष्ट था कि उनका "अवशिष्ट जीवन", किसी भी परिस्थिति में, उनके संबंधित मानक जीवन के एक तिहाई से कम नहीं होगा जैसा कि पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। इस प्रकार, यह प्रतीत होता है कि ऐसे उपकरणों का "अधिग्रहण" जो वापस करने के लिए उपलब्ध थे, एक बिना शर्त अवधि नहीं थी। निगम उन्हें केवल तभी संभालने के लिए बाध्य था जब यह संतुष्ट हो कि उनका "अवशिष्ट जीवन" पक्षों द्वारा निर्धारित मानक जीवन के एक तिहाई से कम नहीं था। ऊपर उद्धृत नियमों और शर्तों से यह स्पष्ट है कि ठेकेदारों को अपनी पसंद के किसी भी समय किसी भी मशीनरी और उपकरण को वापस करने का कोई अधिकार नहीं था, या ऐसा करना सुविधाजनक नहीं था। वे शर्तें जो सभी उपकरणों पर लागू होती हैं, चाहे वे समूह ए में हों या समूह बी में, लेन-देन की प्रकृति निर्धारित करने के लिए भी प्रासंगिक हैं। ठेकेदारों को "कुछ प्रासंगिक विवरण दिखाने वाले उचित मशीन कार्ड को लगातार बनाए रखने की आवश्यकता होती है।" यह उनका कर्तव्य है कि वे उपकरणों को अच्छी स्थिति में बनाए रखें और उन्हें नियमित रूप से और प्रभावी ढंग से सेवा दें। मशीनरी और उपकरणों की किसी भी वस्तु को ठेकेदारों द्वारा किसी भी परिस्थिति में तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक कि उनसे पूरी लागत की वसूली नहीं हो जाती थी और तब भी केवल तभी जब मशीनरी या उपकरणों की उन वस्तुओं को हटाने

से काम की संतोषजनक प्रगति में बाधा आने की संभावना नहीं थी। फिर सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ठेकेदारों को स्वयं निगम द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई गई मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स के अपने स्टॉक को फिर से भरना होगा। जब निगम द्वारा ठेकेदारों को स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति की जाती है, तो वे माल दुलाई, बीमा और सीमा शुल्क सहित उन भागों की वास्तविक कीमत के लिए उत्तरदायी होंगे।

वे महत्वपूर्ण रूप से पक्षों के बीच अनुबंध की शर्तें हैं और इस अपील में निर्धारण के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या निगम द्वारा ठेकेदारों को स्वीकृत रूप से आपूर्ति की गई मशीनरी और उपकरणों के संबंध में, यह केवल भर्ती का अनुबंध था, जैसा कि अपीलकर्ता निगम की ओर से तर्क दिया गया था, या बिक्री या किराया खरीद, जैसा कि प्रतिवादी राज्य की ओर से तर्क दिया गया था। इस विषय पर कानून संदेह में नहीं है, लेकिन पक्षों के बीच लेनदेन का प्रमाण देने वाले दस्तावेज के उचित निर्माण पर किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उस कानून को लागू करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि केवल अधिक के बिना काम पर रखने का अनुबंध, जमानत के अनुबंध की एक प्रजाति है, जो बेली में एक शीर्षक नहीं बनाता है, लेकिन पिछले आधी सदी या मोटे के दौरान किराए की खरीद के कानून में काफी विकास हुआ है और इसमें कई भिन्नताएं आई हैं, इस प्रकार श्रेणियों की ओर ले जाती है, और यह कुछ अच्छाई का सवाल बन जाता है कि पार्टियों के बीच एक विशेष अनुबंध किस श्रेणी के तहत आता है। आम तौर पर, किराया खरीद का अनुबंध अवक्रेता को कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, बल्कि कुछ शर्तों को पूरा करने पर खरीदने का केवल एक विकल्प प्रदान करता है। लेकिन किराया खरीद के अनुबंध में विलंबित भुगतान द्वारा किराए पर ली गई चीज को खरीदने के लिए समझौते के लिए इस शर्त के अधीन प्रावधान किया जा सकता है कि चीज का स्वामित्व तब तक नहीं जाएगा जब तक कि सभी किशतों का भुगतान नहीं किया जाता है। अन्य भी

हो सकते हैं: पार्टियों के बीच सहमत शर्तों के आधार पर किराया खरीद के अनुबंध में बदलाव। जब तृतीय पक्षों में अधिकार पक्षों के कृत्यों या कानून के संचालन द्वारा बनाए गए हैं, तो सवाल, जो यहां उत्पन्न नहीं होता है, यह हो सकता है कि मूल अनुबंध के लिए पार्टियों के अधिकार और दायित्व वास्तव में क्या थे। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि कोई विशेष अनुबंध किस श्रेणी के तहत आता है, अदालत समझौते के सार को देखेगी न कि केवल श्रेणी का वर्णन करने वाले शब्दों पर। यह निर्धारित करने के लिए परीक्षणों में से एक यह है कि क्या कोई विशेष समझौता केवल काम पर रखने का अनुबंध है या क्या यह खरीद मूल्य के स्थगित भुगतान की प्रणाली पर खरीद का अनुबंध है, क्या माल खरीदने के लिए अवक्रेता पर कोई बाध्यकारी दायित्व है। इस तरह के विवाद को निर्धारित करने के लिए एक और उपयोगी परीक्षण यह है कि क्या अनुबंध के निर्वाह के दौरान किसी भी समय माल को वापस करने का अधिकार किरायेदार के लिए आरक्षित है। यदि ऐसा अधिकार सुरक्षित है, तो स्पष्ट रूप से बिक्री का कोई अनुबंध नहीं है, हेल्बी बनाम मैथ्यूज और अन्य (1)। वर्तमान मामले में लेन-देन के लिए इन दो परीक्षणों को लागू करते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कुछ शर्तों पर पुनर्खरीद की शर्त के साथ माल की बिक्री का मामला था जो निगम की संतुष्टि पर निर्भर करता है कि क्या मशीनरी या उपकरण का "अवशिष्ट जीवन" पक्षों के बीच सहमत शर्तों के अनुसार मानक जीवन के एक तिहाई से कम नहीं था। उन शर्तों पर यह स्पष्ट है कि ठेकेदारों को किसी भी समय माल वापस करने का कोई अधिकार नहीं है जब वे इसे सुविधाजनक या आवश्यक पाते हैं। दूसरी ओर, वे पक्षों द्वारा निर्धारित कुल अनुमानित मूल्य का दो-तिहाई समान किशतों में भुगतान करने के लिए बाध्य थे। ठेकेदार किसी भी मशीनरी या उपकरण को वापस करने के लिए शर्तों के तहत बाध्य नहीं थे, न ही निगम उन्हें बिना शर्त वापस लेने के लिए बाध्य था। "अवशिष्ट मूल्य" के भुगतान पर निगम द्वारा मशीनरी या

उपकरणों के "अधिग्रहण" के संबंध में समझौते में शब्द केवल किराए पर लेने के अनुबंध के साथ पूरी तरह से असंगत हैं और ठेकेदारों को माल में संपत्ति के साथ अधिक सुसंगत है, जो खरीद मूल्य की सभी किशतों के भुगतान के अधीन है। इसके अलावा, यह शर्त कि ठेकेदारों को स्वयं, आवश्यकता पड़ने पर, खराब हो चुके पुर्जों को बदलने के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति करनी होगी, भी प्रतिवादी के मामले के अनुरूप है कि मालिकाना हक ठेकेदारों को दिया गया था और वे मशीनरी और उपकरणों के रखरखाव और मूल्यहास के लिए जिम्मेदार थे। यदि यह केवल किराए पर लेने का अनुबंध होता, तो माल का मालिक खराब हो चुके पुर्जों के प्रतिस्थापन और मूल्यहास के लिए उत्तरदायी बना रहता। उन परीक्षणों को पक्षों के बीच समझौते की शर्तों पर लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि लेन-देन स्थगित भुगतानों पर एक बिक्री थी जिसमें पुनः खरीद का विकल्प था, न कि केवल भर्ती का अनुबंध, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया था।

इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से सही है और अपील को लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

अपील खारिज कर दी गई।

Disclaimer:- यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।